PROF. MADHU DANDAVATE: This is exactly what I am telling, Madam. I am not accustomed to violate a single parliamentary procedure. This is due to force of the situation. Within 15 minutes I was required to come here. I can assure you that it will never happen in the future. (*Interruptions*)

Will you please take your seat? I have responded to your suggestion. Kindly take your seat. (*Interruptions*) Shall I request you on bended knees? (*Interruptions*) I am thankful to you for thanking me so angrily. Madam, in my Budget speech on 19th March, I had announced the Scheme for providing debt relief to farmers, artisans and weavers who had taken loans upto Rs. 10,000 from various banks.

I had announced that the Central Government will bear the full responsibility of debt-relief...

श्री मुहम्मद अमीन अंशारी (उत्तर प्रदेश) : मुझे एक बात कहनी है कि एक शब्द इसमें से हटाया जाए। जो आपने 'जुलाहा' शब्द रखा है इसको काट कर 'बुनकर' शब्द लाया जाए।

प्रो. मधु दंडवते : ठीक है, 'बुनकर' कर देता हूं।

I will repeat that again.

I had announced the Scheme for providing debt relief to farmers, artisans and weavers who had loans up to Rs. 10,000 from various banks.

I had announced that the Central Government will bear the full responsibility of debt-relief in respect of loans taken from public sector banks and Regional Rural Banks in the Central sector.

In respect of cooperative banks and land development banks in the States' sector, I am happy to announce that in order to assist the State Governments in regard to debt relief scheme on the Central pattern, the Central Government will bear 50 per cent of the burden of relief on loans taken from these banks in the State sector.

Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: This statement could have been made earlier without such unncessary excitement.

REGARDING INCIDENTS OF FIRE IN SHASTRI BHAWAN —Contd.

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीया, यह जो सिलसिला शुरू हुआ, यह विज्ञान भवन से लेकर, झुग्गी-झोपड़ियों से लेकर, बड़ी बड़ी जगहों पर आग लगी है। शास्त्री नगर में आग लगी और शास्त्री भवन में भी आग लगी। इस बारे में अखबारों में जो बयान छपा है कि कोई विशेष टैरोरिस्ट आर्गेनाइजेशन है उसने इसकी जिम्मेदारी भी है और विज्ञान भवन को जलाने की भी जिम्मेदारी ली है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने उस आर्गेनाइजेशन के बयान के बाद उसकी एक्टीविटीज के बारे में दिल्ली में कोई जांच-पड़ताल की है या उसकी कोई इंक्वायरी की है कि यह आर्गेनाइजेशन कैसे और कब काम कर रहा है? क्या आपने इसका पता लगाया है। यह कहा गया है कि एक हाई लेवल कमेटी जांच पड़ताल के लिए बनी है और यह शास्त्री भवन की आग के बारे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर की देखरेख में होगी। तो मैं चाहता यह हूं कि आग का मामला बड़ा गम्भीर है, यह बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि अभी तक रियल कलप्रिट को पकड़ा नहीं गया है, उनकी धरपकड़ नहीं हुई है। इस लिए क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से आप इसकी जांच पड़ताल करवायेंगे? तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि झुग्गी-झोपड़ियां जल कर खाक हो गई और कुछ लोग मर भी गये, इन लोगों को

फिर से बसाने के लिए क्या सरकार ने कोई जमीन दी है और क्या उनके मकान बनाने के लिए, झौंपड़ियां बनाने के लिए, कोई योजना बनाई गई है ?

SHRI KAMAL MORARKA: Madad, I do not want to take much time. Most of the questions that occurred to me have already been asked by various Members. Some of the questions, I feel, are such which can be answered only in the Police investigation. We had rung up and what was the motive of the fire, if it was a deliberate fire, etc. can come out only in the Police investigation.

I am surprised at only two things in the statement. One is this clearing of corridors of wooden partitions and cupboards. I don't understand it. After all, wood is there all around. I hope there is no proposal to stop using wood. I can see that our Chamber itself is fully wood-panelled. As Mr. Narayanasamy or some other Member said, there is fire hazard in this Chamber also. I do not understand the logic of this decision. If it is only to make way for people to move, it does not matter. But it is not a fire hazard. I don't think a wooden cupboard by itself is a fire hazard. It is in a way. But you cannot stop using wood. What I think is required is to see that electrical short-circuit does not take place and the wiring is done properly. It is a suggestion to the Minister. There is need for a total rechecking and revamping of the electrical system in all these buildings. These buildings are quite old now. Some of these buildings are 30 years old.

The second thing which I cannot understand is that there is a description of the fire. If the Police investigation is still on, the Minister should only tell us when the Police report will come. Only then we would know what had happened. I am supporting the suggestions that the hon. Members have made. All these suggestions should be handed over to the Police to enquire as to what the motive is. There is no use trying to speculate what the motive could be. Members have said two things which I would have liked to avoid in this discussion. One is whether some BJP workers was there or not. Yes, I think you should find out whether he is BJP worker or Congress (I) worker. The second thing is whether the files related to land records or some special records. Yes, you should find out whether those files related to land records of some of the deals which are under enquiry. Yes, we should know it. All these investigations should come out.

I feel that the Minister should be clear about two things. Clearing the corridors of wooden furniture does not make sense. Wooden furniture would be there anywhere. Our Parliament library corridors are full of cupboards. The logic of this decision should be reviewed because wood will be in use. We should take steps to prevent fires and to have fire fighting equipment. I don't think fire fighting equipment is adequate in any of these buildings. There should be an immediate revamping of electrical wiring and we should have fire fighting equipment rather than clearing the furniture from the corridors. Then. one day we will have to clear all the wooden furniture to avoid fire which we cannot afford. Thank you, Madam.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): महोदया, पिछले कुछ दिनों से, पिछले 5-6 महीनों से कश्मीर में तो जबर्दस्त आग लगी हुई है और पंजाब में भी आग लगी हुई है । इस सदन में एक बार इस बात की आशंका व्यक्त की गई थी कि कभी यह आग बढते बढते दिल्ली तक न आ जाय । ठीक वही बात आज सच साबित हो रही है । महोदया, 1.4.4 को आग लगी, 16-4 को आग लगी, 17-4 को आग लगी 30-4 को आग लगी और फिर जो है, कल भी आग लगी और आज भी आग कहीं पर आग लगी है और साथ ही बम

(श्री राम नरेश यादव)

विस्फ़ोट की भी कई घटनायें हुई हैं। महोदया, पहले विज्ञान भवन में आग लगी उसके बाद निर्माण भवन में आग लगी और इससे काफ़ी नुकशान हुआ। जैसा कि यहां पर मेरे मित्रों ने कहा कि समाचार-पत्रों में यह बात प्रकाशित हुई थी कि किसी आतंकवादी संगठन ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस आग को लगाने में हमारा हाथ है। महोदया, मैं इस आधार पर ऐसा समझता हूं कि सरकार ने, जिस तरह के ये सरकारी भवन हैं, शास्त्री भवन मशहूर भवन है, इसमें जो आग लगी इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समाचार-पत्रों में आतंकवदियों द्वारा या आतकवादी सगठनों द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद, सरकार ने इन सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की? अगर सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की तो इसका मतलब यह है कि सरकार, स्वयं, जो इस तरह की घटनायें हो रही हैं, उसके लिये जिम्मेदार है और सरकार विफल है।

दूसरी बात यह है कि ये इतने बड़े भवन हैं, बहुत से सरकारी भवन हैं और आश्चर्य की बात यह है, जहां चिंता होती है वहां आश्चर्य भी होता है और जैसा कि समाचार-पत्रों मे आया है कि जब आग लगी तो वहां से उठते हुए धुएं को एक पासर बाई ने, उस रास्ते से गुजरने वाले व्यक्ति न देखा और उसने इसकी सूचना दी। । मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर, उस भवन में क्या सुरक्षा गार्ड थे या नहीं थे? किसी अधिकारी की देखरेख में वह भवन था या नहीं था? जो सुरक्षा कर्मी वहां पर थे, जो दूसरे कर्मी थे, उसकी हिफाजत करने के लिए, उन लोगों के जरिए क्यों नहीं सूचना दी गई? अगर उनके द्वारा यह सूचना नहीं दी गई तो इससे वह निष्कर्ष निकलता है कि इसमें उनका हाथ है। इस पर भी माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से जवाब देने का काम करेंगे?

तीसरी बात, यह बहुत आवश्यक प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि यह केवल जन लेने का प्रश्न है, यह बहुत महत्वपूर्णव प्रश्न है अभी जैसे हमारे एक साथी ने आशंका व्यक्त की है कि ये जो दोनों सदन हैं इन पर भी खतरा न आ जाय, इसलिए आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर डालने के लिए सरकार काम करे, साथ ही केवल इस तरह से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है कि मामले को पुलिस के हाथों आपने दे दिया कि वह इसकी जांच का काम करे। इसको इस तरह नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से यह बहुत खतरनाक प्रश्न है। यह दिल्ली का प्रश्न है, देश की राजधानी का प्रश्न है। ऐसे स्थान पर इस तरह की घटनायें हों तो निश्चित रूप से इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि इसमें आतंकवादियों का हाथ तो नही है इस बात का पता लगाया जाय ताकि आगे इस तरह की घटनायें न हों। आपके जो अग्नि शमन कर्मी हैं, जो आपकी अग्नि शमन सेवा है, दिल्ली में जिस तरह से ऐसी घटनाओं मे वृद्धि हो रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस सेवा को बढाने का आप काम करें ताकि जब कई जगहों पर इस तरह की आग की घटनायें हों उसमें वे पूरी संख्या में जा सकें। इसके कारण अग्नि शमन सेवा का उपयोग ठीक से नहीं हो पाता है। इसको सक्षम बनाने की आप व्यवस्था करें। साथ ही साथ यह जो रिपोर्ट हुई हैं, मैं जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट करने वाला कौन है? क्यों नहीं रिपोर्ट वहां के किसी अधिकारी ने की? अभी तक उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई हैं? इस संबंध में जूडीशियल इन्क्वारी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज, जो सिटिंग जज हो, उनसे कराने का काम करेंगे या नही करेंगे?

SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL (Punjab): Madam, I just want to know one thing. In the statement, it is said, "a high level committee has already been appointed to enquire into the cause of the fire at Vigyan Bhavan, and also to look into promptness and effectiveness of Delhi Fire Service in tackling the situation."

यह क्या टाइम बाउंड है? कितने दिनों में रिपोर्ट दे देंगे? ऐसा न हो कि

सोजन निकल जाये और उसके बाद रिपोर्ट आए और अगले साल तक बात चली जाय। आप यह बताइये कि क्या यह टाइम बाऊंड है ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : उपसभापति महोदया, राम नरेश यादव जी हम लोगों के बड़े सम्माननीय रहे हैं। उन्होंने सदन की दृष्टि और सरकार की दृष्टि जिस ओर दिलाने की कोशिश की है कि क्या इन सारी घटनाओं के पीछे कोई सुनियोजित षडयंत्र है या यह घटनायें एक के बाद एक ऐसे हो रही हैं, यह गम्भीर सवाल है अगर कहीं राजनैतिक समाधान से ऐसी चीजों का हल हो सके तो यह सरकार की प्रतिबद्धता है कि ऐसी चीजों का राजनैतिक समाधान से हल हो और हम हर एक स्तर पर उसके समाधान की कोशिश करेंगे। निश्चित है कि हर दिशा में हम आगे बढ़ेंगे लेकिन मैं देख रहा हूं कि आग की लपट से भले ही यह सदन न जले लेकिन दिलजलों की लपट से यह सदन जरूर जल रहा है। हम जब राजनैतिक जीवन में आते हैं तो मैं मानता हूं कि कुछ न कुछ मर्यादा, कुछ न कुछ परम्पराओं को निभाने आते हैं **(व्यवधान)**

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Madam, we do not want a lecture. We want answers for our clarifications.

SHRI SUBODH KANT SAHAY: I am giving the answer. (*Interruptions*)

SHRI S. S. AHLUWALIA: Don't make a political speech. (*Interruptions*)

SHRI SUBODH KANT SAHAY: Don't try to pull me. (*Interruptions*) I am giving the answer. (*Interruptions*)

SHRI VISHVJIT P. SINGH: He should know the conventions of the House. (*Interruptions*)

SHRI SUBODH KANT SAHAY: I have every right... (*Interruptions*)

SHRI VISHVJIT P. SINGH: This is not a Gandhi maidan. (*Interruptions*)

श्री सुबोध कान्त सहाय : यह वह सख्स है जो आवाज से दबने वाला नहीं है **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : सत्यपाल मलिक जी इस हाउस की गरिमा को जानते हैं। क्लैरीफिकेशन का जवाब राजनैतिक भाषण नहीं होता है। **(व्यवधान)** गलत बात है **(व्यवधान)**

श्री सुबोध कान्त सहाय : गलत बात नहीं है, 100 प्रतिशत सही है। **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : गलत बात कह रहे हैं। आपको क्लरीफिकेशन पूछे गए आप उनका सीधी तरह से जवाब दीजिए **(व्यवधान)** आप भाषण नहीं दे सकते हैं **(व्यवधान)**

श्री सुबोध कान्त सहाय : हमको बोलने का पूरा अधिकार है **(व्यवधान)** मेरे शब्दों को आप नहीं **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आपको अधिकार नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री सुबोध कान्त सहाय : आपके नेता सीताराम केसरी जी ने राजनैतिक भाषण दिया है **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आपको सिर्फ एक अधिकार सवाल का जवाब देने का और कुछ नहीं। मंत्री को सिर्फ एक अधिकार है सवालों का जवाब देने का और कुछ नहीं **(व्यवधान)**

श्री सुबोध कान्त सहाय : देखिए, या तो चिल्ला लीजिए, उसके बाद मैं बोलूं **(व्यवधान)** आपको क्यों इस बात की तकलीफ है **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप राजनैतिक भाषण नहीं दे सकते हैं।

श्री सुबोध कान्त सहाय : म भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं हकीकत दे रहा (**व्यवधान**) अगर आप अपना कंडक्ट देखिए तो आपको लगेगा कि आप कैसे बिहैव कर रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : अगर आप दो साल पहले इस हाल में रहे होते तो (**व्यवधान**)

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं आपसे ज्यादा समय से राजनीति में हूं (**व्यवधान**) बड़ी गंभीरता से कहना चाह रहा हूं (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : इस हाउस के सारे कनवेंशन तोड़े जा रहे हैं (**व्यवधान**)

डा० अबरार अहमद खान : इन लोगों ने तोड़े हैं (**व्यवधान**)

श्री सुबोध कान्त सहाय : महोदया, इतनी घटनायें घट रही है, उन घटनाओं को ईमानदारी के साथ, गम्भीरता के साथ समझे (**व्यवधान**) हम आज जनता पार्टी में बैठे हुए हैं और हम से आप पूछना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार की बिल्डिगों में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं हुई (**व्यवधान**) उपसभापति महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि (**व्यवधान**)

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Madam, I am on a point of order (*Interruptions*)

श्री सुबोध कान्त सहाय · माननीय सदस्य ने पूछा है कि आज कितनी हाई-राइज बिल्डिगें ऐसी है । (**व्यवधान**)

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, we need your protection. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will allow one person. Shri Vishvjit Singh.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Madam, after the statement was made and before we started seeking clarifications, you made it clear 'Please put only questions: don't make a *bhoomika.*'

श्री सुबोध कान्त सहाय : बहुत भूमिका दी है आप लोगों ने (**व्यवधान**)

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Let me complete....

SHRI SUBODH KANT SAHAY: Don't teach too much....I will not tolerate it.

SHRI KAMAL MORARKA: I agree with my friend.. (*Interruptions*)

श्री सुबोध कान्त सहाय :.. (व्यवधान) यह गलत तरीका है । आप अपना तरीका देखिए ..(व्यवधान) मैं भी आपसे चाहता हूं । अपना तरीका देखिए । दूसरों को समझा रहे हैं .. (**व्यवधान**)

उपसभापति : उनका तरीका अगर आपको गलत लग रहा है तो आपका भी तरीका गलत है । अगर मैंने इजाजत दी है बोलने की .. (**व्यवधान**) आप बैठे रहिए ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : ये मंत्री हैं .. (**व्यवधान**)

श्री सुबोध कान्त सहाय : ... (**व्यवधान**) इसलिए आपकी बात से दब जायेंगे । मंत्री होना कोई गुनाह नहीं है (**व्यवधान**)

उपसभापति : मंत्री जी, ठण्डे दिल से । गुस्सा नहीं करना है । हम लोग ... (**व्यवधान**) आज की बात कर रहे हैं यह थोड़ी है कि हम लोग भी इतने गरम हो जायेंगे ।

श्री सुबोध कान्त सहाय : आई विल नाट टालरेट इट .. (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : ... (**व्यवधान**)

उपसभापति : आज भी देखिए, अपने तरीके को जरा देख लीजिए ... (**व्यवधान**) आप भी बगैर मेरे पूछे खड़े हो जाते हैं । यह भी कोई गरिमा की बात नहीं है । अगर किसी ने गलती की है, अगर पास में किसी दूसरे ने गलती की है, आपके कहने के मुताबिक तो क्या जरूरी है कि आप भी वही गलती करें इसलिए बेहतर है कि आप बगैर मेरी इजाजत के नहीं बोलें, अगर यह मामला सीरियस आप समझते हैं कि आतंकवाद का मामला है और गम्भीरता का मामला है । आपने कुछ एलीगेशन लगाये हैं, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं । मैं उनसे यह निवेदन करूंगी कि वे आपके जो क्लेरीफिकेशन हैं उनका जवाब दें, क्योंकि पौने सात बजे रहे हैं, लेट बहुत हो गया है इसलिए सवालों का जवाब दें । आप क्या बोल रहे थे ।

SHRI VISHVJIT P. SINGH: I agree with you. You have said what I wanted to say.

श्री सुबोध कान्त सहाय : हमारे माननीय सदस्यों ने यह सवाल पूछा कि यहां पर कितनी ऐसी बिल्डिगें हैं जिनमें फायर प्रोटेक्शन की पूरी व्यवस्था नहीं है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 158 ऐसी बड़ी इमारतें हैं । मैं कहना चाहता हूं कि सही में पिछली लम्बी अवधि से, दसियों सालों से ज्यादा, इसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए थी, कहीं कहीं कुछ कार्यवाही करके उन्हें पूरी तरह से इक्विपड बनाना चाहिए था । लेकिन यह नहीं हुआ । इसमें 50 प्रतिशत सरकारी बिल्डिगें हों यह भी मैं बताना चाहता हूं क्योंकि आगे कोई घटना घटे अतः इसकी हकीकत इस सदन को जाननी चाहिए और उस 50 प्रतिशत में 36 बिल्डिगें सैन्ट्रल गवर्नमेंट की हैं, 13 लोकल बाडीज की हैं और 30 आटोनामस बिल्डिगें हैं, और भी इसी तरह से बिल्डिगें है जिनमें तरह से व्यवस्था नहीं है ।

उपसभापति महोदया : 12 तरह के इक्विपमेंटस पूरी तरह से फायर प्रूफ बनाने के लिए लगाये जाते हैं । सी०पी०डब्ल्यू०डी० शायद 900 लाख का प्रोपोजल पिछले काफी दिनों से लेकर बैठी हुई है । सरकार ने कुछ हद तक इनको उपलब्ध कराया है जिससे टम्पोरेरी बासिस पर काम किया जा रहा है । लेकिन दसियों और पन्द्रहों सालों से ये प्रोपोजल पड़े हुए हैं और इनका नतीजा आज नेशनल फ्रंट सरकार की उपलब्धि में आया है । हम धुंआ देख रहे हैं, तुरंत उसे बुझाना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी लाचारी है । इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है ।

हमारे साथियों ने पूछा है कि कितनी जगहों पर आग लगी । मैं बताना चाहता हूं कि हाल के दिनो में विज्ञान भवन, गांधी नगर मार्केट, सदर बाजार, मोतिया खान, शाहबाद झुग्गी झोंपड़ी, आदर्श नगर झुग्गी, गीता कालोनी, जहांगीरपुरी, सलिमपुर, शाहबाद और दलालपुर, शास्त्री नगर आदि इतनी जगहों में, झुग्गी झोंपड़ियों में आग लगी है...

श्री जगेश देसाई : विजय घाट की झोंपड़ियों में कल लगी है ।

श्री सुबोध कान्त सहाय : अभी तक उसके बारे में हमारे पास खबर नहीं है । मैं उस मामले में कहना चाहूंगा कि अगर वहां आग लगी है और लोगों ने हमें खबर नहीं दी है तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस अधिकारी पर तुरंत अनुशासनहीनता की कार्यवाही मैं करूंगा ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : सिर्फ दो सौ झुग्गियां जली हैं ।

श्री सुबोधकांत सहाय : इनमें 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, शाहबाद दलालपुर झुग्गी के इलाके में, जो कि ऐसी अवस्था में पकड़े गये है । लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने कहा कि बी०जी०पी० के कार्यकर्ता हैं... । सरकार के पास किसी बी०जे०पी० के

कार्यकर्ता या किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के गिरफ्तार होने का कोई सबूत नहीं है। हम लोग हरेक एंगल से इसकी जांच करवाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : इसका सबूत हम देंगे।

श्री सुबोध कान्त सहाय : : हम इसकी जांच करवाना चाह रहे हैं और हमने दिल्ली प्रशासन के साथ बैठ कर, उसके तमाम इंटेलिजेंस अफसर, प्रशासन के अफसर, पुलिस के अफसर, फायर ब्रिगेड से संबंधित बहुत सारे लोगों की मीटिंग बुला कर हरेक स्तर पर चाहे वह बम का सवाल हो या आग लगने का सवाल हो, इसको मानीटर किया है और इस पर कार्यवाही हो रही है। हम कोई भी ऐसा शक जहां मिलता है, उस दिशा में जांच चल रही है।

अभी हम यह निर्धारित नहीं कर पाये हैं कि यह आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला है या सही में कुछ दिल जले लोगों के द्वारा किया जा रहा है।

शास्त्री भवन में जो कल की घटना हुई है, उसमें डिप्टी कमिश्नर आफ पुलिस के माध्यम से यह इक्वायरी हो रही है और जैसा कि मैंने कहा कि इस पर काबू पा लिया गया है। तीन-चार करोड़ की वह पूरी बिल्डिंग है। ग्राउन्ड फ्लोर और उसके बाद प्लेन था और उसके बाद फिर फर्स्ट और सैकण्ड फ्लोर का जो टाप है, जिसमें आग लगी है, उसका भी 60 प्रतिशत जला है।

जो लोग कह रहे हैं कि रात को आग लगी है। अगर रात से आग लगी होती, तो उसके नीचे टेलीफोन एक्सचेंज है और उसके बाद और भी सारी चीजें हैं। ऐसी चीजें थीं जिसमें कि नुकसान होता। लेकिन जिस फ्लोर में आग लगी है, उसका 60 प्रतिशत ही जला है।

वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित विभाग था। किस तरह, कितना वहां नुकसान हुआ है, क्योंकि वह सारी चीजें इंक्वायरी के तहत है, इसके बारे में अभी हमारे पास पूरा आकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम गंभीरता के साथ कहना चाह रहे हैं कि इसको हम रेगुलर रुटीन में नहीं देख रहे हैं, बल्कि सरकार के पास चुनौती है और मैं चाहूंगा कि इस चुनौती में, दिल्ली पूरे देश की राजधानी है, इसकी गरिमा में अगर हमें आप सब साथियों का सहयोग और यहां के माननीय सदस्यों का सहयोग मिला, तो यह बड़ी बात होगी।

विज्ञान भवन के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसके तीन सदस्य हैं--श्री पी० एन० मल्होत्रा, फामर फायर आफिसर, भारत सरकार, श्री एन० के० सिंघल, रिटायर्ड आई०पी०एस०, श्री बी० बी० नंदा, चीफ इंजीनियर, एन०डी०एम०सी०--यह तीन लोगों की कमेटी बनाई गई है, और यह जल्द ही अपनी रिपोर्ट देने वाले हैं, जिससे कि सारी चीजों का पर्दाफाश किया जा सकेगा।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : इस कमेटी का कोई टाईम निर्धारित किया है कि कितना है?

श्री कमल मोरारका : जैसा पहले हुआ करता था।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : फिर अच्छा है।

श्री सुबोध कान्त सहाय : हमने फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी घायल हुए हैं, उनको दस हजार रुपये का इनाम दिया गया है और साथ ही साथ उनका पूरा मेडिकल खर्च जब तक वह अस्पताल में हैं, उनके सारे खर्च की जिम्मेदारी सरकार ने ली है और दस हजार रुपया उनकी बहादुरी और उनकी निष्ठा के लिए उनको इनाम दिया गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी यह पूरी कोशिश है कि चाहे वह प्रधान मंत्री का निवास स्थान हो, चाहे वह विपक्ष के नेता का 10-जनपथ हो, अगर किसी

स्तर पर भी हमें जरा सी भी गुंजाइश लगती हो कि इसमें ढिलाई है, तो उसकी हम फिर से जांच करवायेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि देश में सही अमन और न चैन हो और यह आगकी लपटें कम हों।

इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Madam, I seek your indulgence.

SHRI JAGESH DESAI: Who made this call? Was it an employee or was it an outsider who informed the Fire Brigade?

श्री सुबोध कान्त सहाय: यह तो पुलिस का इनवेस्टिगेशन है।

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Madam, only two very small points I would like to ask. One very, very small point is about the amount of area which has been burnt in the *jhuggi jhonpri* colonies and, No. 2 linked with that, the files of the lands stored in the Bhavans. And I do know it for a fact that on the top floor of Nirman Bhavan where the record room is, there are files of the lands. How much of the land files are destroyed? That is no. 1 No. 2. How much of the land is cleared through these files in the *jhuggis*?

श्री सुबोध कान्त सहाय: मैं आपको चिट्ठी से खबर कर दूंगा।

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Thank you very much.

उपसभापति: अगर आपके पास अभी खबर नहीं है, तो आप पता लगा कर इनको जवाब दे दीजिए। हाउस में जवाब दे दीजिएगा।... **(व्यवधान)**

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह: जब मंत्री जी इतने बढ़िया तरीके से बोलते हैं तो हम भी बढ़िया तरीके से सुनते हैं। यह भेद-भाव की कोई बात ही नहीं है। बिना वजह यह नाराज हो जाते हैं। पता नहीं क्या बात है।... **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: यह नाराज सब से ज्यादा मेरे से होते हैं, क्योंकि हम दोनों एक मोहल्ले के हैं।

SPECIAL MENTIONS—CONTD.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now special mentions. Shri Syed Sibtey Razi. Prof. Sourendra Bhattacharjee. Smt. Margaret Alva. Shri M. C. Bhandare. Shri Gurudas Das Gupta. Shri Ish Dutt Yadav. Dr. Nagen Saikia. Shri Shabbir Ahmad Salaria.

Need to include Gujars Bakarvals and Gaddis of Jammu and Kashmir and Argoons of Ladakh etc. in the list of Scheduled Tribes

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): In the State of Jammu and Kashmir.... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't be so discourteous as not to listen to the special mention.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: The erstwhile Government of Jammu and Kashmir had made a thorough survey and thereafter recommended for recognising certain sections of the society as Scheduled Tribes under the Constitution of India. Among the sections which had been recommended by the Government of Jammu and Kashmir are Gujars, Bakarvals and Gaddis of Jammu and Kashmir and Argoons of Ladakh along with others. It so happened that when the recommendation reached the Government of India, a policy of pick and choose was resorted to, and without assigning any reasons, Gujars, Bakarvals and Gaddis of Jammu and Kashmir and Argoons of Ladakh who happen to be generally Muslims, were